1	2	3	4
6.	Gujarat	2774.47	2718.03
7.	Madhya Pradesh	2641.84	2553.4
8.	Maharashtra	6130.24	6967.42
9.	Rajasthan	1623.23	1342.35
10.	Goa	31.73	36.29
11.	Haryana	2206.73	804.33
12.	Punjab	3436.46	1667.68
13.	Uttar Pradesh	8036.28	4497.79
14.	Himachal Pradesh	44.70	76.28
15.	Jammu & Kashmir	33.74	43.98
16.	Bihar	2054.93	1433.05
17.	Orissa	398.91	1251.42
18.	West Bengal	3610.77	3857.61
19.	Assam	151.49	229.24
20.	Tripura	48.71	20.89
21.	Manipur	—	17.06
22.	Meghalaya	8.76	13.51
23.	Sikkim	1.32	2.82
24.	Mizoram	—	0.9
	TOTAL:	51401.56	43464.48

इस्पात विकास निधि

533. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस्पात विकास निधि के अन्तर्गत मार्च, 1995 तक 4521.63 करोड़ रुपए की राशि उगाही गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निधि से विभिन्न मदों के लिए कतिपय राशि भी स्वीकृत की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस्पात के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए और अधिष्ठापित इस्पात उत्पादन एककों के विकास हेतु ऋण के रूप में अब तक कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है;

(घ) इस समय उक्त निधि में कुल कितनी राशि अभी शेष है; और

(ङ) विगत वर्षों में इस निधि से दिए गए ऋण पर ब्याज की औसत दर कितनी-कितनी रही है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) प्रमुख उत्पादकों को उनकी आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाओं के वित्त-पोषण हेतु इस्पात विकास निधि (एस०डी०एफ०) से ऋण मंजूर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस्पात विकास निधि को अन्य उद्देश्यों जैसे अनुसंधान कार्यक्रमों के लिएनिधियन, लघु उद्योग निगमों को रियायत देना तथा संयुक्त संयत्र समिति के इकॉनोमिक रिसर्च यूनिट (ई०आर०यू०) से संबंद्ध व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाना है।

(ग) चूंकि इस्पात विकास निधि द्वारा वित्त-पोषत प्रमुख कार्य-कलापों में अनुसंधान और विकास कार्य नहीं था इसलिए दिनांक 31-3-95 का अध्ययन एवं सर्वेक्षण (निम्न वाष्पशील मध्यम कोककर कोयले की जांच) के लिए केवल 5 लाख रुपए की राशि ही व्यय की गई। इस्पात विकास निधि प्रबंधन समिति ने 9 करोड़ रुपये की लागत की अकोककर कोयले के उपयोग से लौह अयस्क

चूरे से इस्पात तैयार करने के लिए रेजीनेस प्रक्रिया-प्रौद्योगिकी के विकास के निधियन हेतु प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

(घ) इस्पात विकास निधि का संग्रह मुख्य रूप से प्रमुख इस्पात उत्पादकों को दिए गए ऋणों के रूप में है। दिनांक 1-4-95 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया ऋण लगभग 5090 करोड़ रुपये था। जबकि दिनांक 31-1-96 को निधि में शेष नकद मात्र 2.82 करोड़ रुपये था।

(ङ) इस्पात विकास निधि प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित ब्याज दरें निम्नानुसार हैं:—

उत्पादन से सीधे जुड़े, ऋणों पर 8%, तथा

अवसंरचना कार्यों से संबंधित ऋणों पर 5%

Target for the production of steel

534. SHRI JANESHWAR MISRA:
SHRI NAGAMANI:
SHRMATI MALTI SHARMA:

Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) the target fixed for the production of steel during Eighth Five Year Plan;

(b) whether a large number of mini steel plants have been closed; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) The anticipated production of finished steel by 1996-97, the terminal year of Eighth Five Year Plan, is about 23.8 million tonnes.

(b) Yes, Sir.

(c) The Electric Arc Furnace industry, also known as mini steel plants, is characterised by a pre-dominance of small sized furnaces which are not able to adopt modern technological features. Coupled with this, labour, financial and managerial problems faced by these units led to the closure of a number of units over a period of time. In addition, their performance has been adversely affected by the rise in the international prices of scrap which constitutes their basic raw material and other factors like high power tariff.

Schemes for welfare of minorities

535. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2809 given in Rajya Sabha on 22nd December, 1995 and state:

(a) the details of the schemes and programmes which have so far been implemented for the welfare of minorities in the country;

(b) whether Government have a proposal to provide some special incentives to them; and

(c) if so, what are the full details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) The 15-Point Programme for welfare of minorities announced in 1983 is being implemented at the Centre and State levels. The Programme on visages various welfare measures including safety and security of life and property and schemes for their socio-economic and educational upliftment. The details of the various schemes which are being implemented are as follows:

The scheme of pre-examination coaching for weaker sections based on economic criteria is being implemented by the Ministry of Welfare as a Central scheme for the target groups consisting of OBCs and minorities with the objective of increasing their in-take in Government services and professional institutions.

The National Minorities Development & Finance Corporation is implementing schemes for promotion of self-employment ventures for the backward sections among minorities through various State Channelising Agencies. They are providing loans at concessional rates.